प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | ■ वर्ष : 61 ■ अंक 03 ■ 15 दिसंबर 2024 ■ पृष्ठ-12 ■ मूल्य - 3.00

प्रकाशन के 6 दशक

1 साल की हुई मोहन सरकार

जो 2 दशकों में न हुआ उसे सालभर में कर दिखाया

पेज- 02

शिंदे-सोरेन फार्मूले पर केजरीवाल का सियासी गणित

महिलाओं के लिए खोला खजाना

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खोली *सीआई कविता शर्मा की कुंडली*

फर्जी प्लाट आवंटन को लेकर सीआई की खोली पोल, कविता को बचाने वाले अधिकारियों का भी करेंगे खुलासा

पेज- 08

सदन में मिले माननीयों के आश्वासनों पर अमल में *लापरवाही*

सैकड़ों की संख्या में उत्तर आने का इंतजार कर रहे हैं प्रश्न

जीतू पटवारी ने किया ऐलान

16 दिसंबर को विधानसभा घेराव में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत

पेज- 03

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में दरार

राहुल गांधी से दूरी बनाने लगे हैं इंडिया गठबंधन के साथी दल?

सपा ने छोड़ा महाविकास अघाड़ी का साथ, ममता भी नाराज, लालू यादव भी पलटे

समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा कांग्रेस का स्टैंड

पेज- 05

जरा ये धूप ढल जाए तो हाल पूछेंगे,
यहां कुछ साये अपने आप को खुदा बताते हैं।

4 महीने पहले आरएसएस ने तय किया... फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री

पेज- 09

मुंबई में तय हुआ महाराष्ट्र का 'किंग'

देवाभाऊ बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री

पेज- 10

बिहार में *अलर्ट पर* जेडीयू!

शिवसेना जैसा खेल, खेल सकती है भाजपा

महाराष्ट्र में कुर्सी की अदला-बदली पर बिहार में हलचल, 2025 में नीतीश का क्या होगा?

पेज- 11

1 साल की हुई मोहन सरकार

जो 2 दशकों में न हुआ उसे सालभर में कर दिखाया

भोपाल। पूरे देश का मीडिया मध्य प्रदेश बीजेपी के दफ्तर पर नजर गढ़ाए बैठा था। मौका था मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री को चुनने का। दफ्तर के बाहर मीडिया का हुजूम था, अंदर नेताओं का। घड़ी की हर बढ़ती सूई के साथ नेताओं, उनके समर्थकों और फिर मीड़िया की धुकधुकी बढ़ रही थी। संशय ये था कि पिटारे में से किसका नाम निकलेगा। दौड़ में जो नाम थे उनमें खुद शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार विजय पाई, सांसदी और केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद सिंह पटेल, कई सालों बाद चुनाव लड़े कैलाश विजयवर्गीय। आखिर वो समय आया, पिटारे से नाम निकला और जो नाम निकला, वो था डॉ. मोहन यादव। डॉ. मोहन यादव उस दिन ग्रुप फोटो के लिए तीसरी लाइन में बैठे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका नाम भी रेस में है। उस दिन कई लोगों के चेहरे खिले और कईयों के मुरझाए। 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और फिर शुरु हुआ चुनौतियों का सिलसिला।

भाजपा दफ्तर में जब सीएम मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के एक साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया कि डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था, क्योंकि सीएम मोहन के नेतृत्व में इस सरकार ने मध्य प्रदेश में कई बड़े फैसले किए हैं जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। क्योंकि सीएम मोहन यादव के सामने चुनौतियां कई थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब तक यह साबित किया है कि बीजेपी आलाकमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सही था।

मध्य प्रदेश के लिए अहम रहा एक साल

सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, जिनकी चर्चा जनता के बीच भी हो रही है। शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल में भी नहीं हुए थे उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया।

मध्य प्रदेश-राजस्थान के बीच
सुलझा जल बंटवारे का मुद्दा

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले 20 सालों से चंबल-कालीसिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था, सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर भी खास फोकस किया, खास बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर फोकस दिखाया, ऐसे में दोनों राज्यों के सीएमों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठकर यह मुद्दा सुलझाने पर फोकस किया, जिससे 20 साल पुराना यह विवाद सुलझ गया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू पर भी साइन हो गए हैं। पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी की लिंकिंग परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना को फायदा होगा। 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, इसके अलावा पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी प्रदेश में पानी आएगा।

महिलाओं को
35 प्रतिशत आरक्षण

महिलाओं 35 प्रतिशत आरक्षण देने का मोहन सरकार का फैसला भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसलें के तहत अब मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत की जगह 35 प्रतिशत पदों पर आरक्षण मिलेगा। इसी तरह मोहन सरकार ने कोयला आवंटन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है, जहां वह केंद्र सरकार से 41000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को स्वीकृति दिलाने में सफल रहे। इससे मध्य प्रदेश में 25000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रदेश में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी मोहन सरकार ने किया है जिसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटवाना, सीपीए को बहाल करना, राज्य परिवहन निगम फिर से शुरू करने जैसे फैसले भी शामिल हैं।

अफसरशाही पर लगाम

मध्य प्रदेश में सीएम मोहन अफसरशाही को लेकर भी सख्त दिखे। उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी चर्चा न केवल एमपी में बल्कि देश में भी हुई, 2023 में गुना में बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसके बादस सीएम मोहन ने गुना के कलेक्टर तरुण राठी, एसपी विजय खत्री को हटाया और परिवहन आयुक्त संजय झा भी जिम्मेदारी से हटा दिया। इसी तरह शाजापुर में भी तत्कालीन कलेक्टर किशोर कन्याल का 'औकात' वाला वायरल हुआ तो लगे हाथ कार्रवाई हुई और कलेक्टर को हटाया गया। देवास में भी इसी तरह का मामला सामने आया था जहां फसल को लेकर किसान और तहसीलदार आमने-सामने आ गए, तहसीलदार ने किसान के बेटे से कहा 'चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं और बड़ी-बड़ी मारने लगे' इसके बाद लगे सीएम मोहन ने यहां भी एक्शन लिया। सिंगरौली के चितरंगी में महिला से जूते के फीते बंधवाने वाले एसडीएम को भी हटाया गया था, जबकि सागर के शाहगढ़ में हुए दीवाल हादसे के बाद यहां के कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिरी थी।राजनीतिक जानकारों का भी यह मानना है कि सीएम मोहन यादव ने एक सख्त प्रशासक की छवि अपनाई थी, जिसमें उन्होंने एक तरह से यह तय किया कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की जनता के प्रति हैं, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी जनता के प्रति है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सबसे ज्यादा फोकस जनता के लिए ही करना है।

मध्य प्रदेश में आ रहा निवेश

सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह सरकार लगभग हर महीने ही संभागीय उद्योग सम्मेलन करवा रही है। इंदौर, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम और सागर जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। उज्जैन में हुए उद्योग सम्मेलन में ही 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव आया, जिससे यह अभियान सफल माना गया। इसी तरह जबलपुर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़, ग्वालियर में 1।84 लाख करोड़, सागर में 23,000 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें सागर के सुरखी में खोले जाना वाला डेटा सेंटर और स्टील प्लांट जैसे काम भी शामिल है। रीवा के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी 31,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे, जबकि सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे पर भी 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। इससे इस सरकार की उपयोगिता को समझा जा सकता है। नर्मदापुरम में बीते दिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में काफी बड़ी संख्या में देश- विदेश के निवेशक और उद्योगपति शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में प्रदेश को 31, 800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अकेले इंग्लैंड से आए एक निवेशक ने राज्य में 500 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जाहिर की है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में निवेश की वृद्धि होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसके साथ प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों का जीवन बदलने का काम करना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सियासी मोर्चे पर भी सफल हुए सीएम मोहन

सीएम मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल साबित हुए बल्कि वह राजनीतिक मोर्चे पर भी सबसे सफल रहे। 2023 में सरकार बनने के बाद सीएम मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहां उन्होंने 100 प्रतिशत सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां तक की देशभर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यह काम बड़े-बड़े राजनीतिक धुरंधर नहीं कर पाए थे, लेकिन मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 26 साल बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढहा दिया। ऐसे में सीएम मोहन यादव की कार्यकुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं। हालांकि सरकार को अभी एक साल पूरा हुआ है, फिलहाल उनके सामने कई चुनौतियां है तो कई अवसर भी हैं, जिसमें सरकार कैसे चलती है यह तो समय ही बताएगा।

सदन में मिले माननीयों के आश्वासनों पर अमल में लापरवाही

भोपाल। जनहित से जुड़े मामलों को विधायक समय-समय पर विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाते हैं। सदन में उठाए जाने मामलों के बारे में माना जाता है कि एक बार कोई सवाल पूछ लिया गया , तो उसका समाधान होना तय है, लेकिन प्रदेश की अफसरशाही इसे गंभीरता से नहीं लेती है। शायद यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में प्रश्नों के उत्तर आने का इंतजार समाप्त ही नहीं होता है।

सैकड़ों की संख्या में उत्तर आने का इंतजार कर रहे हैं प्रश्न

इसी तरह की स्थिति सरकार द्वारा सदन में मंत्रियों के माध्यम से दिए जाने वाले आश्वासनों की भी है। अब प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र इसी महीने 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होने जा रहा है। सत्र की घोषणा के बाद शासन स्तर पर विभागों ने पिछले सत्रों के अपूर्ण उत्तर, आश्वासन, शून्यकाल और लोक लेखा समिति की सिफारिशों की पड़ताल शुरू कर दी है। बीते हफ्ते मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विधानसभा सत्र को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उसमें चौंकाने वाले आकंड़े समाने आए हैं। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि संबंधित विभाग विधानसभा के अपूर्ण उत्तरों को पूर्ण करने में रुचि नहीं ले रहे हैं और न ही संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों को ही पूरा किया है। बैठक में सामने आया है कि 2 दिसंबर की स्थिति में शून्यकाल के 43% मामले लंबित हैं। इसी तरह 995 प्रश्नों के अभी तक जवाब नहीं दिए गए हैं। 886 आश्वासनों पर संबंधित विभागों ने कोई काम ही नहीं किया है। वहीं विधानसभा की सबसे प्रमुख समितियों में गिनी जानी वाली लोक लेखा समिति की 66 सिफारिशों को भी नहीं माना गया है। ये सभी मामले में कार्यपालिका (शासन) स्तर पर लंबित हैं।

शून्यकाल

2 दिसंबर की स्थिति में शून्यकाल की 43 सूचनाएं लंबित हैं जबकि 18 जून 2024 की स्थिति में 39 मामले लंबित थे। इनमें सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की 12, लोक निर्माण विभाग की 6, पंचायत एवं ग्रामीण विकास 4, स्कूल शिक्षा 4, स्वास्थ्य विभाग में शून्यकाल के 3 प्रकरण लंबित हैं।

अपूर्ण उत्तर

मौजूदा स्थिति में 995 प्रश्नों के जवाब विधायकों को नहीं मिले हैं। जून में यह संख्या 939 थी। जिनमें सबसे ज्यादा कृषि विभाग 166, सामान्य प्रशासन 123, राजस्व 93, नगरीय विकास 60, सहकारिता 58, जनजातीय कार्य 49; वित्त 48, जल संसाधन 33, स्कूल शिक्षा 30, अनुसूचित जाति कल्याण 25, परिवहन 24, उच्च शिक्षा 21, धार्मिक न्यास 20, पंचायत 16, खनिज विभाग ने 12 सवालों के जवाब नहीं दिए हैं।

आश्वासन

विधानसभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए 886 आश्वासन्नों को पूरा नहीं किया गया है। जून में यह संख्या 1085 थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 193, जनजातीय कार्य 67, स्वास्थ्य 63, लोक निर्माण 52. राजस्व 49, स्कूल शिक्षा 42, सहकारिता 42, पंचायत 39, कृषि 35, वन 33, सामान्य प्रशासन 20, उच्च शिक्षा 18, जल संसाधन 17, उद्यानिकी 15, परिवहन 10 और खाद विभाग के 10 आश्वासन लंबित हैं।

सिफारिशें

विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक लोक लेखा समिति द्वारा की गईं 66 सिफारिशें लंबित हैं। इनमें वाणिज्यिक कर 24, राजस्व 13, लोक निर्माण 8, संस्कृति 5, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 3. पशुपालन विभाग 3, वन 2. नर्मदा घाटी 2, पर्यावरण विभाग से जुड़ी 2 सिफारिशें लंबित हैं।

20000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान 17 दिसंबर को करीब 20 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इस संबंध में कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा।

इस साल राज्य का वार्षिक बजट जुलाई में पेश किया गया था, जिससे पहला अनुपूरक बजट पेश होने में देरी हुई। विधानसभा सत्र में सरकार का एक मुख्य उद्देश्य अनुपूरक बजट और विधेयक लाना होगा। वित्त विभाग ने अक्टूबर ने अनुपूरक बजट की तैयारी शुरू कर दी थी। सभी विभागों को अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

यह तय किया गया कि अनुपूरक बजट के लिए किस आधार पर प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। विभागों को नए वाहन खरीदने के संबंध में प्रस्ताव न भेजने को कहा गया। विभागों को यह भी बताने को कहा गया है कि ऋण और अनुदान के रूप में कितनी राशि मिलेगी।

जीतू पटवारी ने किया ऐलान

16 दिसंबर को विधानसभा घेराव में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत

प्रदेश की विधानसभा का घेराव कर कांग्रेस साल 2024 का सबसे बड़ा आंदोलन होने का दावा कर रही है। इसे लेकर ब्लॉक स्तर तक तैयारी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में भोपाल लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा इस घेराव प्रदर्शन में निष्क्रिय रहने वाले जिला अध्यक्षों की छुट्टी भी हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का सबसे बड़ा घेराव करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहले पैदल मार्च करेंगे। इसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस घेराव में ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में भोपाल लाया जाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस कमेटी के शहर और जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जो नेता इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेगा, उसे संगठन से हटाया भी सकता है, भले ही वह नेता शहर जिला अध्यक्ष क्यों ना हो ?

आंदोलन को लेकर बीजेपी का पलटवार

इस आंदोलन की घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। डॉ. मोहन यादव सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। मंत्री सारंग ने कहा कि हमेशा से कांग्रेस ने विश्वासघात किया है जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने हर वादे को पूरा कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के घेराव को लेकर सरकार दावा कर रही है कि लोग सरकार के साथ है इसलिए ऐसे आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस कर रही है आंदोलन

प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संकल्प पत्र 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर आंदोलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने को लेकर किसानों को खाद न मिलाना, अपराधों का बढ़ना, बेरोजगारी बढना आदि मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश

विजयपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। इसके बाद से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार आंदोलन और प्रदर्शन की घोषणाएं की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के जरिए उन कांग्रेसी नेताओं को भी रोकने की कोशिश की जा रही है जो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।

मालव 50 स

साइबर अपराध का खतरा

देश में साइबर अपराध किस तरह पैर पसार चुका है, इसका पता गृह मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) के खुलासे से चलता है, जिसके मुताबिक, नवंबर तक साइबर धोखाधड़ी की 12 लाख शिकायतें आयीं, जिनमें से 45 प्रतिशत मामलों को कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से अंजाम दिया गया। वर्ष 2021 में गठित सीएफसीएफआरएमएस ने साइबर धोखाधड़ी के 30.05 लाख मामलों का खुलासा किया है, जिनमें 27,914 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके मुताबिक, 2021 में साइबर धोखाधड़ी की 1,35,242, 2022 में 5,14,741 और 2023 में 11,31,221 शिकायतें आयीं।

ऐसे ही, इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर तक साइबर धोखाधड़ी से देश को 11,333 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस दौरान स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों में सर्वाधिक 2,28, 094 शिकायतें आयीं और 4,636 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। निवेश से जुड़े मामलों में 1,00,360 शिकायतें आयीं और 3,216 करोड़ का घोटाला हुआ, डिजिटल अरेस्ट की 63,481 शिकायतें मिलीं और 1,616 करोड़ का नुकसान हुआ। डिजिटल अरेस्ट के जरिये अकेले इस साल की पहली तिमाही में 120.3 करोड़ रुपये की क्षति हुई।

साइबर हमलों में ऑनलाइन फ्रॉड और सेक्टार्शन जैसी चीजें ही शामिल नहीं हैं। इनमें डाटा चोरी, रैनसमवेयर, ऑनलाइन हेट क्राइम, साइबर बुलिंग, अवैध सट्टेबाजी एप, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर साइबर अटैक आदि शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। साइबर अपराधों के खिलाफ देश में अलग से कानून नहीं है और आइटी एक्ट में संशोधन के तहत 2022 में लाये गये प्रावधानों के जरिये इन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। साइबर अपराधों के विरुद्ध केंद्र ने साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी) और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का गठन किया है।

हाल ही में आतंकवाद-विरोधी एक कॉन्फ्रेंस में आइ4सी ने साइबर धोखाधड़ी मामलों की जांच में चुनौतियों का जिक्र किया। दूरसंचार मंत्रालय के सहयोग से उसने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से संचालित होने वाले 17,000 संदिग्ध व्हाट्सएप अकाउंट बंद भी किये हैं। विगत अगस्त में संसद सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने कहा था कि अन्य अपराधों की तरह साइबर अपराध रोकना भी राज्य की जिम्मेदारी है। सच यह है कि साइबर अपराध रोकने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित कानून बनाने के साथ केंद्रीय स्तर पर साइबर आर्मी और राज्यों में साइबर पुलिस का गठन समय की मांग है।

दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर भारत

ललित गर्ग

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत एवं उसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की साख एवं सीख के कारण भारत दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 5 दिन के विदेश दौरे में तीन देशों की यात्रा की और 31 ग्लोबल लीडर्स और वैश्विक संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। मोदी की विदेश यात्राओं से विश्व में भारत का न सिर्फ सम्मान बढ़ रहा है बल्कि दुनिया का हमारे देश के प्रति नजरिया भी बदल रहा है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि दुनिया के शीर्ष ताकतों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्न देशों को छोटे-छोटे देशों के हितों का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। प्रधानमंत्री के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र इस बात की ओर ही संकेत है। भारत में वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, युद्धमुक्त दुनिया बनाने, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर दुनिया की अगुवाई करने की क्षमता है। इस पहलू को अब दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां भी स्वीकार करने लगी हैं। मोदी ने बार-बार कहा है भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से काम करता है, जिसमें छोटे-छोटे देशों के हितों को पूरा करने के लिए समान विकास और साझा भविष्य का संदेश भी निहित है, जो भारत की आशावादी एवं समतामूलक सोच को दर्शाता है।

भारत को स्वर्णिम भारत, अच्छा भारत, रामराज्य का भारत या दुनिया का सिरमौर इसलिये कहा जाता है कि यह वो देश है जहाँ से दुनिया ने शून्य को जाना। खेल, पर्यटन और फिल्मों से जिसको पहचाना जाता है। जिसकी अंतरिक्ष में पहुँच, तकनीकी प्रतिभाओं से विश्व ने भी भारत का लोहा माना है। बिना रक्त क्रांति के जिसने पायी थी आजादी। भारत दुनिया को बाजार नहीं, एक परिवार मानता है। संतों के सान्निध्य में चलने वाली भारत की व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन हैं। मानव सभ्यता के 95 प्रतिशत समय तक भारत दुनिया को खनिज, मसाले और धातुओं के साथ ही धर्म, गणित एवं खगोलशास्त्र की अवधारणाएं देता रहा। जब सारी दुनिया भटकती है तब भारत उसका मार्ग प्रशस्त करता है। भारत टकराव और संघर्ष को मानवता के लिए खतरा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दौर में हमें अपने अस्तित्व ही नहीं, सम्पूर्ण मानवता के लिए लड़ने की जरूरत है। भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए हमेशा ही ये संदेश दिया है कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, गरीबी, आतंकवाद, युद्ध और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है।

आज दुनिया में ऐसी ही संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण की चर्चा हो रही है जहां समाज कल्याण एवं जीडीपी विकास दोनों का सह-अस्तित्व हो और नागरिकों की प्रसन्नता सर्वोपरि हो। भारत ऐसी ही अर्थव्यवस्था यानी संवेदनशील वैभव के सदुपयोग को खुशहाल जीवन और दीर्घकालिक आत्मनिर्भर समाज का आधार मानते हुए आगे बढ़ रहा हैं। भारतीय सभ्यता सदा से धन और दान दोनों को सर्वोच्च मानती है। हमारे ऋषियों-मनीषियों ने वाकपटुता, सहायता करने की तत्परता, शत्रुओं से निपटने की बुद्धिमत्ता, स्मृति, कौशल, नैतिकता एवं राजनीति का ज्ञान आदि गुणों को सफल नेतृत्व का आधार बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हीं गुणों के बल पर भारत को दुनिया में अव्वल स्थान पर पहुंचाया हैं। भारत के पास सबसे मजबूत लोकतंत्र है, विविधता है, स्वदेशी एवं समावेश सोच, आदर्श जीवनशैली, वैश्विक सोच है और दुनिया इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों का समाधान देख रही है।

आज अमेरिका अपनी गिरती साख को लेकर चिन्तीत है। यूरोपीय संस्कृति ऐसी रही है, जिसमें उन वस्तुओं पर भी पैसा बहाया गया, जिनकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं थी। चीन ने कारोबार और नीतियों का ऐसा रास्ता अपनाया, जिसमें कोई नैतिकता नहीं। रूस अपने शत्रु को आंकने में गलती कर गया और एक अंतहीन से युद्ध में उलझकर रह गया। दुनिया में मची इस उथल-पुथल के बीच ऐसा लगता है कि केवल भारत ही ऐसी प्रमुख शक्ति है, जिसने ऐसा रास्ता चुना जो कूटनीतिक समझ और नैतिकता से भरा है। साथ ही, उसने एक स्थिर अर्थव्यवस्था के वैश्विक ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया है, जिसके साथ दुनिया व्यापार करना चाहती है। ये सब इसी कारण संभव हुआ, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, हमारा नेतृत्व संस्कृति से जुड़ा एक महान् कर्मयोद्धा कर रहा है। दुनिया पिछले हजारों सालों से सुखों के लिए दौड़ रही है लेकिन इस दौड़ में हार चुकी है। अब उसकी नजर भारत पर है। देश को अपनी सारी शक्ति एकजुट करनी होगी। सारी दुनिया में कट्टरपंथ और उदारता के बीच लड़ाई चल रही है। कपट और सरलता के बीच संघर्ष चल रहा है। देश को अपने मूल्यों को स्थापित करने के लिए सेनापति की भूमिका निभानी होगी और उसके लिये उसकी तैयारी भी है।

वर्तमान में भारत आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बन रहा है, यह अच्छा संकेत है। अन्यान्य क्षेत्रों के साथ भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसलिए सारा संसार भारत की ओर बड़ी आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। परन्तु अनेकानेक विशेषताओं एवं विलक्षणताओं के बीच कुछ विसंगतियां एवं विषमताएं भी हैं। भारत की अस्मिता का प्रतीक मातृशक्ति की आज सर्वत्र अवमानना की जा रही है। चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता से जूझता हुआ हमारा भारतीय समाज भोगवादी संस्कृति का आदी हो चुका है। अपने देश में भारत के हित में विचार करनेवाले, समाज की उन्नति के संबंध में चिंतन करनेवाले लोगों की कमी नहीं है। फिर भी आज देश की व्यवस्था में राष्ट्रभक्तों का अभाव दिखता है, संकीर्ण राजनीति एवं सत्ता की दौड़ में मूल्यों को धुंधलाने की स्थितियां कमजोर करती है। यही कारण है कि संपूर्ण देश में एक असंतोष की भावना दिखाई देती है। सरकारी यंत्रणाओं के प्रति जनमानस का विश्वास प्राय: लुप्त होता जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में नये परचम फहराने वाले युवाओं, घर को संस्कारों से संवर्धित करनेवाली नारीशक्ति, संपूर्ण भारत के जीवन को पोषित करनेवाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों तथा खेतों, कारखानों तथा सर्वत्र मजदूरी करनेवाले श्रमिकों, वन-संस्कृति का जतन करनेवाले वनवासी भगिनी-बंधुओं के आत्मविश्वास, लगन तथा परिश्रम के जागरण से भारत दुनिया में अव्वल होने की दिशा में अग्रसर है। देश का शिक्षित, प्रबुद्ध तथा समृद्ध समाज को दीन-दलितों, अशिक्षितों तथा असहाय लोगों के उत्थान के लिए आगे आना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन डेलायट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक भारत के चीन और अमेरिका जैसी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में उभर कर सामने आने की आशा व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मध्यम वर्ग का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण बाजार तक पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। व्यापार की नीतियों में उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने का असर उपभोक्ता बाजार पर दिख रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के निर्यात में बढ़ोत्तरी ने भी उपभोक्ता बाजार का आकार बढ़ाने में सहायता की है।

हमें राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सामरिक दृष्टि से सबल बनाना होगा। भारत को दुनिया का सिरमौर देखने की कामना करने वाले लोगों से अपेक्षा है कि वे जागे, कुछ नया और अनूठा करें। आनेवाली पीढियां तुम्हें निहार रही हैं। भारत का भविष्य अब युवाओं पर ही निर्भर है। उठो, जागो और समस्त दायित्व अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। जितनी शक्ति और सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर है। अत: अपना भविष्य स्वयं गढ़ों। मानव चिंतन के शीर्ष पर रहने वाला भारतीय समाज 300 वर्षों के अंतराल के बाद अपने ऐतिहासिक गौरव को फिर से पाने के पथ पर अग्रसर है। मध्यकाल में राह भटकने के बाद आज देश की युवा पीढ़ी एक ऐसे भारत में आगे बढ़ रही है, जो अवसर, संस्कृति और प्रगति का देश है।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में दरार

राहुल गांधी से दूरी बनाने लगे हैं इंडिया गठबंधन के साथी दल?

सपा ने छोड़ा महाविकास अघाड़ी का साथ, ममता भी नाराज, लालू यादव भी पलटे

नई दिल्ली। 'इंडिया' में गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, इस सवाल का जवाब लोकसभा चुनाव के पहले नहीं मिला लेकिन नतीजों के बाद इसका आधा जवाब मिला। जवाब भी आधा ऐसा जिसे खुलकर कोई नहीं बोल रहा था लेकिन राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में आ गए। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी की ओर से 400 पार की बात की जा रही थी लेकिन नतीजों के बाद वह अपने दम पर बहुमत से भी पीछे रह गई। नतीजों ने विपक्ष में एक जोश भर दिया और इसके केंद्र में राहुल गांधी आ गए। जून के महीने में जैसे गर्मी का पारा चढ़ता है कुछ वैसा ही लोकसभा नतीजों के बाद तेजी से राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ता है।हालांकि अक्टूबर आते-आते जैसे मौसम बदलता है ठीक वैसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहा है। अक्टूबर में हरियाणा और नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद 'इंडिया' में गठबंधन में ही राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

विपक्षी गठबंधन का गठन जून 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा हटाओ, देश बचाओ के नारे के साथ किया गया था। तब इसके अगुआ जनता दल यूनाइडेट के नेता नीतीश कुमार थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पाला बदला और भाजपा के एनडीए से हाथ मिला लिया। इसके बाद गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी दलों ने नीतीश पर खूब हमला बोला था। मगर नीतीश वापस नहीं लौटे। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू की। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था। भाजपा की सीटें कम हुईं तो विपक्षी गठबंधन में जोश दिखा।

मगर जैसे-जैसे राज्यों के चुनाव हुए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में मतभेद शुरू होने लगे। मौजूदा मामला महाराष्ट्र से आया है। यहां समाजवादी पार्टी ने शिवसेना (उद्धव) नेता द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस की प्रशंसा करने के बाद महाविकास अघाड़ी (एमवीए) छोड़ने की घोषणा की है। इससे पहले अदाणी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं दिखीं। विपक्षी गठबंधन में सबसे यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अब कई पार्टियां गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने लगी हैं। कांग्रेस को लेकर विपक्षी दलों का मानना है कि उसे आत्मचिंतन करना चाहिए और दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। इसी का नतीजा है कि सहयोगी दल कांग्रेस के दबदबे के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब सभी की निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर टिकी हैं।

- **मॉनसून सत्र से शीतकालीन सत्र आते ही सब कुछ बदल गया:** लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मॉनसून सत्र में जहां पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा था वही शीतकालीन सत्र आते मानो विपक्षी एकता की गर्माहट गायब हो गई। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक टीएमसी की ओर से किया जाता है। टीएमसी की ओर से कहा गया कि अब वक्त आ गया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं अडानी मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने मोर्चा खोला तो वहीं टीएमसी पीछे हटते हुए दिखी। कांग्रेस को टीएमसी का बिल्कुल भी साथ नहीं मिला।
- **ममता और केजरीवाल अलग राह पर:** टीएमसी सवाल खड़े कर रही है तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी पुरानी राह पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा हुई लेकिन गठबंध नहीं हुआ। जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो कांग्रेस पर सवाल उठे। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने नसीहत दी कि यदि साथी दलों को मिलाकर लड़े होते तो नतीजे कुछ बेहतर होते। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से पहले ही यह ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा और पार्टी अकेले लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर लड़े थे तो वहीं विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं।
- **बीजेपी अपनी पिच पर खिलाने लगी विपक्ष को:** राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में अपने हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा विपक्ष अडानी मुद्दे पर उनकी हां में हां मिलाए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सपा और टीएमसी वैसे भी कांग्रेस की इस वाली राजनीति से सहमत नहीं। विपक्ष के भीतर भी एक विपक्ष नजर आ रहा है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि पूरा विपक्ष किसी मुद्दे पर एकजुट हो और वैसा ही हो रहा है। साथ ही कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी स्थिति इंडिया गठबंधन में कमजोर हुई है। ममता बनर्जी की ओर से जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है।
- **ममता बनर्जी ने जताया था असंतोष:** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। सपा और ममता बनर्जी के बयान से साफ हो गया है कि अगर समस्या का हल नहीं निकाला गया तो सभी दलों को इंडिया गठबंधन में एक साथ रहना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। हाल ही में लालू यादव ने भी ममता के पक्ष में बयान देकर सब को चौका दिया है। इसलिए अब लीडरशिप को लेकर उठाए आवाज से इंडिया गठबंधन के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा कांग्रेस का स्टैंड

अडानी मुद्दे को जहां कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है वहीं समाजवादी पार्टी खुलकर इस मुद्दे पर उसके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन में भी सपा के सांसद नजर नहीं आए। यूपी उपचुनाव में ही दोनों के बीच कड़वाहट देखने को मिली भले ही खुलकर किसी भी दल की ओर से कुछ नहीं बोला गया। वहीं अब संभल मुद्दे पर सपा को कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश सपा को रास नहीं आई। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संभल मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। टीएमसी और सपा के साथ ही इंडिया गठबंधन के कुछ और साथी भी कांग्रेस का बिना नाम लिए सवाल उठा रहे हैं। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कहा था कि वे सांप्रदायिकता छोड़ देंगे और धर्म निरपेक्ष ताकतों से हाथ मिलाएंगे। उन्होंने और उनकी पार्टी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों का सम्मान किया है। समाजवादी पार्टी उनके साथ कभी नहीं रह सकती जो लोगों को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें एमवीए की समन्वय बैठक के लिए कभी नहीं बुलाया गया। हम लोकसभा चुनावों की तरह समन्वय चाहते थे लेकिन कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और राकांपा (एसपी) सीट बंटवारे को लेकर एक-दूसरे से लड़ते रहे। यही कारण है कि महाराष्ट्र चुनाव हम हार गए।

11 दिसम्बर - 26 दिसम्बर 2024

जनकल्याण पर्व

जनसेवा और मध्यप्रदेश के विकास के लिए निष्ठा और समर्पण का एक साल

त्वरित निर्णय बने मिसाल

मुख्यमंत्री **डॉ. मोहन यादव द्वारा**

₹758 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण

"मैं प्रदेश के आठ करोड़ नागरिकों का आभारी हूं, जिनके सहयोग से हमारा प्रदेश आज अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प के तहत, प्रदेश 'GYAN' गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के चार मुख्य स्तंभों पर आधारित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ रहा है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

"गरीब, युवा, महिला और किसान, 'विकसित भारत' के लिए हम इन चारों स्तंभों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने में जुटे हैं। देश में सिर्फ चार जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं। मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं।
मेरा मानना है कि मूल आस्था और धर्म को छोड़कर इन चार मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा।"

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

समृद्ध हो रही संस्कृति

- मकर संक्रांति से गीता जयंती तक पूरे वर्ष के त्योहारों को प्रदेश सरकार ने समाज के साथ मिलकर मनाया।
- विक्रम सांस्कृतिक पर्व का 1 मार्च से 9 अप्रैल, 2024 तक आयोजन। कालजयी महानायकों पर केन्द्रित भारत के पहले संग्रहालय "वीर भारत न्यास" का शिलान्यास।
- विक्रमोत्सव पर विश्व की पहली "विक्रमादित्य वैदिक घड़ी" का शुभारंभ कर प्रदेश ने भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया।
- रक्षाबंधन पर बहनों के सम्मान में पूरे श्रावण माह प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों ने बढ़ाई भाई-बहन के स्नेह की प्रतिष्ठा।
- गुरुजनों के सम्मान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। अब हर वर्ष होगा गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन।
- 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय।
- श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों (सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापाव इंदौर एवं अमझेरा धार) को जोड़ कर श्रीकृष्ण पाथेय का होगा निर्माण। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पाठ्यक्रमों में रामायण और गीता वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल।
- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर मध्यप्रदेश में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन निर्माण का निर्णय।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
- मां क्षिप्रा शुद्धिकरण एवं प्रवाहमान बनाए रखने का संकल्प पूरा करने के लिए ₹ 599 करोड़ की लागत की कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन।

सुशासन की सरकार

- नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिये साइबर तहसील लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, साइबर तहसील 2.0 प्रारंभ।
- ई-पंजीयन एवं ई-स्टेम्पिंग के माध्यम से संपत्ति रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 शुरू।
- राजस्व महाअभियान के दो चरणों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम और सीमांकन के 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा, राजस्व महाअभियान 3.0 प्रारंभ।
- थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य सम्पन्न।
- हर जिले में होगा पुलिस बैंड।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण एवं युक्तिकरण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित।
- 1972 के नियम को बदलते हुए सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान स्वयं करने का निर्णय।
- सुलभ आवागमन के लिए परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर बने चैक पॉइंट।
- खुले में मांस, मछली की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध।
- भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय।
- लाउड स्पीकर की अनियंत्रित एवं अनियमित आवाज का प्रयोग किया प्रतिबंधित।
- वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य।

नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को सफल बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प पूरा किया।
- जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभूतपूर्व पहल पर जलगंगा संवर्धन अभियान का आयोजन। पर्यावरण दिवस (5 जून) से गंगा दशहरा (16 जून) तक चला अभियान। ₹ 1384 करोड़ की लागत से 56 हजार से अधिक जल स्त्रोतों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।
- 18 लाख से अधिक नागरिकों ने की जनभागीदारी।

अभूतपूर्व गति से औद्योगिक विकास

- वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में किया गया घोषित ।
- अब तक सम्पन्न हुईं 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम से रु. 2.07 लाख करोड़ एवं मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में किये गये रोड-शो कार्यक्रमों में ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में ₹ 20 हजार करोड़ के निवेश और यू.के. और जर्मनी की यात्रा में ₹ 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से कुल ₹ 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनसे 3 लाख से अधिक रोज़गार सृजित होंगे।
- प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र प्रारंभ किये गए।
- मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना का निर्णय।
- नर्मदापुरम जिले के मुहासा-बाबई इंडस्ट्री एरिया में रिन्युबल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित उपकरणों की इकाइयों का भूमिपूजन।

आगे बढ़ते युवा

- युवाओं की शिक्षा एवं आधुनिक तकनीकों में योग्यता और कौशल निर्माण के साथ सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवा शक्ति मिशन प्रारंभ।
- सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर की जा रहीं भर्तियां। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती का लक्ष्य। पदों की भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर होगा जारी।
- भारत सरकार के पीएलएफ सर्वे में मध्यप्रदेश ने दर्ज की सबसे कम बेरोज़गारी दर।
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में 20 हजार चयनित युवाओं को लगभग ₹ 41 करोड़ स्टाइपेंड वितरित ।
- स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹ 50 हजार से लेकर ₹ 1.50 लाख तक वित्तीय सहायता।
- अग्निवीर योजना में युवाओं का चयन हो, इसके लिए 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य। मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को मिलेगा आरक्षण।
- प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय।
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्गत सभी जिलों में बनेंगे खेल स्टेडियम।।
- भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।
- वर्तमान में कुल 268 शासकीय आई.टी.आई. संचालित। इस वर्ष 22 नये आई.टी.आई. प्रारंभ करने से 5280 अतिरिक्त सीट्स की होगी वृद्धि।

जनजातीय समाज को समान अधिकार

- छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लायओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाने जायेंगे।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय ₹ 3000 प्रति बोरा से बढ़ाकर किया ₹ 4000 ।
- पीएम जन-मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में ₹ 7300 करोड़ से अधिक की लागत से हो रहे अधोसंरचना कार्य। 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित।
- पीएम जन-मन योजना अन्तर्गत देश में सर्वप्रथम जन-मन कॉलोनी शिवपुरी में बनाकर मध्यप्रदेश योजना में अग्रणी। देश की सबसे पहली जन-मन सड़क बालाघाट जिले में बनकर तैयार।
- युवाओं को यूपीएससी, पीएससी, सिविल जज, गेट, कैट आदि के लिए निःशुल्क कोचिंग का निर्णय।

गरीब वर्ग को समान अवसर

- इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को ₹ 224 करोड़ की लंबित राशि का भुगतान।
- संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को ₹ 895 करोड़ से अधिक का अंतरण।
- स्वामित्व योजना में 24 लाख भू-अधिकार पत्र वितरित कर प्रदेश देश में प्रथम।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹ 10 हजार से 50 हजार तक ऋण सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 55 लाख हितग्राहियों को ₹ 3 हजार करोड़ से अधिक राशि का अंतरण।
- 5 करोड़ पात्र हितग्राहियों को 30.59 लाख मी.टन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत वितरित
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों को एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर।

खुशहाली की ओर अन्नदाता

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को ₹ 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत ₹ 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम ₹ 3900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता।
- वर्ष 2024-25 बजट में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान। लगभग 32 लाख कृषक हो रहे हैं लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-23' में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹ 750 करोड़ से अधिक की राशि के दावों का हुआ भुगतान।
- किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान।
- सोयाबीन का ₹ 4,892 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय।
- 5 वर्षों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन दाल शुरू किए जाने का निर्णय। अरहर, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों के एमएसपी पर उपार्जन की व्यवस्था बनेगी मजबूत।

आत्मविश्वास से भरपूर नारी शक्ति

- नारी सशक्तिकरण के प्रति सम्मान स्वरूप वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक का जबलपुर में आयोजन।
- मां अहिल्या बाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष एवं विजयादशमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में हुए दशहरा शस्त्र पूजन कार्यक्रम।
- दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय बनाने का निर्णय।
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को मिलेगा अब 35 प्रतिशत आरक्षण।
- लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक ₹ 19 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण।
- प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को ₹ 450 में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में ₹ 715 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख महिलाओं को मिली धुएं से मुक्ति।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना में दिसम्बर 2023 से अब तक 5 लाख 12 हजार बालिकाओं को ₹ 170 करोड़ की छात्रवृत्ति अंतरित।
- स्व-सहायता समूह के अंतर्गत लखपति दीदी योजना से महिलाएं बन रहीं सशक्त और आत्मनिर्भर। 1 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति।
- 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख बहनें हुईं आत्मनिर्भर।
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को ₹ 275 करोड़ का अंतरण।
- सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को ₹ 57 करोड़ 18 लाख की राशि अंतरित।
- जेंडर बजट में ₹ 19 हजार 21 करोड़ से अधिक की वृद्धि। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन के विभागों को ₹ 1 लाख 21 हजार करोड़ का प्रावधान।

सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

- उज्जैन को मिली मध्यप्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात। मेडिसिटी में सुपरस्पेशिलिटी एवं मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल, चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र जैसी अनेक सुविधाएं होंगी उपलब्ध।
- पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल।
- आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल, ₹ 1381 करोड़ का प्रावधान।
- वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित। 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन एवं पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र प्रारंभ होंगे।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण बना।
- स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों (नियमित/ संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति।
- जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को एक-एक शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय।

सशक्त भविष्य के लिए शिक्षा

- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ।
- 369 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज़ विद्यालयों का संचालन, वर्ष 2025 में लगभग 150 नये सीएम राइज़ विद्यालय होंगे संचालित।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश। नई नीति के तहत वर्ष 2025 से लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में छोटे बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी प्रारंभ होगी।
- ₹ 170 करोड़ से खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन।
- सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ।
- शिक्षा को वैश्विक संस्थानों से जोड़ने के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एम.ओ.यू.।
- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा।

कायाकल्प की ओर शहरी विकास

- यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।
- प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जायेगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा-राजगढ़ को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।
- भारत सरकार के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी।
- संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्वीकरण तथा पुनर्विकास नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी। जिसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में लाभ से वंचित सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।
- खाली मिलों जैसे हुकुमचंद/विनोद मिल एवं अन्य शहरों में खाली पड़ी शासकीय भूमियों पर शहरी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जायेंगे।
- निर्माणाधीन महाकाल महालोक उज्जैन, संत रविदास लोक सागर, माँ नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, देवी लोक सलकनपुर, श्री रामराजा लोक ओरछा, जाम साँवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, श्री परशुराम लोक जानापाव, महाराणा प्रताप लोक भोपाल, भादवामाता लोक नीमच, माँ पीताम्बरा लोक दतिया और माता मंदिर लोक रतनगढ़ को पूरा किया जायेगा।

नयी पहचान गढ़ता पर्यटन

- "पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा" का शुभारंभ। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली, उज्जैन एवं खजुराहो के मध्य शुरू हुआ संचालन।
- मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं।
- मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता कॉरिडोर।
- प्राणपुर, सावरवानी एवं लाडपुर खास को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार।

सेवा और संवर्धन गौ-संरक्षण

- वर्ष 2024 गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक गांव 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
- 10 से ज्यादा गाय पालने पर शासकीय अनुदान देने का निर्णय।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ एमओयू। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करने लगेंगी।
- ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना।
- प्रत्येक 50 किमी पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध। 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ।

विकास को बल देती अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2024-25 में 16% की बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत
- अगले 5 साल में बजट को दोगुना करते हुए ₹ 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य
- आगामी वित्त वर्ष में शून्य बजट का प्रावधान करने का निर्णय।

प्रगति का आधार अधोसंरचना विकास

सड़क

- इंदौर में ₹ 350 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर।
- ₹ 10 हज़ार करोड़ से अधिक की 724 किमी लम्बी विभिन्न 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 3 हजार 500 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए ₹ 5 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति। इसके निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्र मुम्बई-दिल्ली 8 लेन इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर से जुड़ेंगे।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 गांव 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से बारहमासी मार्ग से जुड़े।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 हजार कि.मी. की सड़कों के निर्माण एवं लगभग 2 हजार कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य।
- ₹3589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति।
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत।

वायुसेवा

- ग्वालियर से बेंगलुरु, अहमदाबाद, ग्वालियर, दिल्ली और अयोध्या के लिए विमान सेवा प्रारंभ।
- विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। रीवा में मध्यप्रदेश का छठवें एयरपोर्ट का शुभारंभ।
- ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन।

रेल

- ₹ 14440 करोड़ की लागत से भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल निर्माणाधीन।
- इंदौर-उज्जैन के मध्य शुरू होगी वन्दे मेट्रो ट्रेन।
- ₹ 18 हजार 36 करोड़ की इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति, 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशनों से जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजनांतर्गत 33 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास एवं 133 रेल ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
- मध्यप्रदेश को 364 विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश को चौथी सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन) ट्रेन मिली।
- भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव और सुविधाओं के विकास हेतु लगभग ₹ 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास।

नवीकरणीय ऊर्जा

- 12 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली उत्पादन 14 गुना बढ़कर हुआ 7,000 मेगावॉट।
- 308 करोड़ रुपये की लागत से खरगौन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का भूमिपूजन।
- ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से 278 MW विद्युत उत्पादन प्रारंभ।
- इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए हर घर सोलर अभियान का संचालन।
- मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा
- शाजापुर, आगर और नीमच में सोलर पार्क का निर्माण।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 दिसम्बर को छतरपुर में परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- परियोजना से प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा
- प्रदेश की कुल 41 लाख आबादी होगी लाभान्वित

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 दिसम्बर को परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- प्रदेश के मालवा क्षेत्र के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना में 6.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा।

अन्य सिंचाई परियोजनाएं

- ₹ 1320 करोड़ की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। सिंगरौली जिले में परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।
- ₹ 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।
- प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित, वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य।

शिंदे-सोरेन फार्मूले पर केजरीवाल का सियासी गणित

नई दिल्ली। आधी आबादी को अपने हक में करने के महाराष्ट्र व झारखंड के कामयाब फार्मूले को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी आजमाया है। केजरीवाल ने भी दोनों राज्यों की तरह महिलाओं को 2,100 रुपये देने का वायदा किया है। इस दिशा में एक कदम बढ़ते हुए आप की दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी भी दे दी है। इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र व झारखंड सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी इस चुनावी वायदे के सहारे दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की कोशिश कर रही है।

महिलाओं के लिए खोला खजाना

हालांकि, दिल्ली में इससे पहले भी 2019 विधान सभा चुनाव में इस तरह का एक सफल प्रयोग किया गया था। विधान सभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस में महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया था। इसका असर भी विधान सभा चुनाव के दौरान दिखा। आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान महिलाओं ने पुरुषों के करीब-करीब बराबर ही वोट किया था। पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 62.59 व महिला मतदाताओं को प्रतिशत 62.52 था। वहीं, करीब 25 विधान सभाओं में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया।

सियासी पंडित बताते हैं कि महिलाओं को बतौर वोट बैंक में तब्दील करने का यह पहला बड़ा प्रयोग था। इसका सीधा फायदा आप को हुआ था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आप को वोट किया। इससे आप ने दूसरी बार बड़ी हासिल की थी। इस बार उनके पास महाराष्ट्र व झारखंड के कामयाब उदाहरण भी हैं। इसमें दोनों राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के खाते में सीधे पैसा डालने की योजनाएं घोषित कर फिर से सत्ता हासिल कर सकीं थीं। इसी भरोसे केजरीवाल ने पहले से घोषित योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2100 करने का दावा किया है।

इस तरह की योजनाओं ने महिलाओं में जाति व धर्म का बंधन कमजोर किया है। वहीं, इससे महिलाएं वोट बैंक के तौर पर तब्दील होंगी। इसका फायदा उन दलों को ज्यादा होता है, जिनकी सरकार है और वह इसी तरह की किसी योजना को लागू कर रही है। इसमें यह बात अलहदा है कि चुनावों से पहले इस तरह की घोषणाएं एक तरह से प्रलोभन होती हैं।

इनको मिलेगा योजना का फायदा

- दिल्ली के स्थाई निवासी हों
- वोटर कार्ड दिल्ली का हो
- 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं इसमें शामिल होंगी
- सरकारी कर्मचारी इसके दायरे से बाहर होंगे
- निजी नौकरी करने वाली महिला अगर आयकर देती हैं तो उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा
- किसी दूसरी योजना की लाभार्थी इसकी पात्र नहीं होंगी
- योजना लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराने के साथ स्वघोषित हलफनामा देना होगा कि वह योजना की पात्र हैं

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खोली सीआई कविता शर्मा की कुंडली

फर्जी प्लाट आवंटन को लेकर सीआई की खोली पोल, कविता को बचाने वाले अधिकारियों का भी करेंगे खुलासा

जयपुर। राजस्थान की सियासत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सीआई कविता शर्मा की तकरार का बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इस दौरान अपने खिलाफ पुलिस में शिकायत के बाद किरोड़ी कविता शर्मा पर जमकर बिफर गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता शर्मा के फर्जी प्लाट आवंटन के आपराधिक मामले को लेकर पूरा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कविता और उनकी बहनों की जन्म तिथि को लेकर भी सवाल उठाए। यही नहीं किरोड़ी ने अपनी ही सरकार के साथ पिछली गहलोत सरकार को भी जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वह उन बड़े लोगों के नाम जल्द उजागर करेंगे, जो कविता शर्मा को बचा रहें है, लेकिन उससे पहले प्रदेशाध्यक्ष से बात करेंगे। किरोड़ी के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में सनसनी फैला दी है।

किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता शर्मा को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कविता की पूरी कुंडली खोज निकाली। इसको मीडिया में दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में एफआईआर 525 के जरिए कविता के खिलाफ धोखाधड़ी से प्लाट हड़पने का झोटवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। इसमें पीड़ित महिला शकुंतला मूंदड़ा ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें कविता शर्मा ने अपनी गलत जन्म तिथि बताकर फर्जी तरीके से जमीन का आवंटन करवा लिया।

कविता ने रचा जमीन आंवटन के लिए षडयन्त्र

किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि कविता के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है। उसके अनुसार 1982 में कविता की उम्र 4 साल थी, जबकि उसने अपनी जन्मतिथि 1978 बताई। इसी तरह उसकी छोटी बहनें सुचिता और पुनीता की भी क्रमश: 9 और 2 साल की उम्र थी। इस मामले में कविता ने अपना जवाब पेश किया कि उसकी बचपन में ही सगाई हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि जब तक शादी नहीं होती, तब तक उनके पति का नाम प्रॉपर्टी में दर्ज नहीं हो सकता। वहीं, जो मामला कविता के खिलाफ दर्ज है, उसमें उसके पति का चंद्रशेखर शर्मा का नाम लिखा है। इसी तरह पुनीता के पति का नाम चंद्रशेखर व्यास और सुचिता के पति का नाम रामलाल शर्मा दर्ज किया है। इससे साफ साबित होता है कि कविता शर्मा ने फर्जी तरीके से बेकडेट में जमीन का आवंटन करवाया।

किरोड़ी ने बताया कविता शर्मा कितनी असरदार है

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कविता शर्मा को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि कविता शर्मा कितनी असरदार है, इसका पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी बाल बांका नहीं हुआ और न हीं इस सरकार में कोई कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि कविता शर्मा के खिलाफ मामले की चार्ज शीट में कविता के खिलाफ अपराध प्रमाणित हुआ है। जिसके चलते वह गैर जमानती मामले के तहत गिरफ्तार होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। किरोड़ी ने बताया की कविता ने 2011 में जेडीए में भूखण्ड के नियमन के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह कागज गलत थे।

कविता को बचाने वाले अधिकारियों को कठोर दंड मिले

किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कविता शर्मा के साथ उसे बचाने वाले अधिकारियों को भी जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीआईडी सीबी ने जुर्म प्रमाणित माना है, लेकिन दबाव के चलते अधिकारियों ने इस प्रकरण को बंद कर दिया और चार्ज शीट में से कविता का नाम निकाल दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार चार्ज शीट में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोई की परमिशन के बाद ही कोई नाम निकाला जा सकता है। उन्होंने नाम हटाने वाले अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 166 ए और धारा 160 ए का हवाला देते हुए कहा कि लोक सेवक यदि विधि की अवज्ञा करता है, तो उसे 6 माह का कठोर कारावास देने का प्रावधान है। ऐसे में जिसने कविता का नाम हटाया, उसे भी सजा मिलनी चाहिए।किरोड़ी ने कविता शर्मा के पीछे बड़े लोगों का हाथ होने की बात कही। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरोड़ी लाल मीणा ने कविता शर्मा के पीछे बड़े नाम के हाथ होने की बात उजागर की। इस पर जब मीडिया ने उन नाम को जानना चाहा, तो किरोड़ी ने कहा कि मैं पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात करूंगा, उसके बाद में इनका नाम उजागर करूंगा।

4 महीने पहले आरएसएस ने तय किया... फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री

शिंदे ने इमेज बचाने के लिए वक्त लिया, सरकार बनने की इनसाइड स्टोरी

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी तीसरी पारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक सोर्स ने 11 दिन पहले ही बता दिया था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे।इसकी स्क्रिप्ट चुनाव के ऐलान से 4 महीने पहले अगस्त में लिख ली गई थी। आरएसएस और बीजेपी ने फॉर्मूला तय किया था कि अगर महायुति की सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। किसी वजह से अगर सरकार नहीं बन सकी, तो देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा।

बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि शिंदे और अजित पवार को पहले से पता था कि महायुति की सरकार बनने पर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तभी बहुमत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे तो अमित शाह ने उनसे मुख्यमंत्री पद के बारे में कोई चर्चा नहीं की।सवाल ये है कि अगर सब कुछ तय था, तो महाराष्ट्र में सरकार बनने में इतनी देरी क्यों हुई। शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों आ रही थीं। इस स्टोरी में पढ़िए, फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की कहानी और इन सारे सवालों के जवाब।

पीएम मोदी ने 2022 में फडणवीस से वादा किया था, अब पूरा किया

- आरएसएस के एक सोर्स बताते हैं कि फडणवीस शुरुआत से प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद रहे हैं। 30 जून, 2022 को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए, तब पीएम मोदी के कहने पर ही फडणवीस ने डिप्टी मुख्यमंत्री का पद मंजूर किया था। पीएम मोदी ने तभी वादा किया था कि अगली बार सत्ता में आने पर फडणवीस को सम्मानजनक पोजिशन दी जाएगी।फडणवीस ने तब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल में बड़ी जगह बनाई थी। इसी का नतीजा है कि वे दोनों के करीब हैं। अब उनके हाथ में मुख्यमंत्री और फिर बीजेपी अध्यक्ष बनने का विकल्प है। बीजेपी से जुड़े एक सोर्स बताते हैं कि 23 नवंबर को आए रिजल्ट में महायुति को बहुमत मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था। उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई तक दे दी थी।

इमेज खराब न हो इसलिए एकनाथ शिंदे ने लिया लंबा वक्त

- अब सवाल ये है कि सब तय था तो एकनाथ शिंदे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि वे नाराज हैं। कभी वे अपने गांव चले गए, तो कभी लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया। यहां तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह दिया- 'मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं और जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं।' इसका जवाब महाराष्ट्र की सियासी नब्ज समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विनोद राउत देते हैं। वे कहते हैं, 'महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी ने शिवसेना को नजरअंदाज किया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे बीजेपी को सबक मिला कि राजनीति में अपने सहयोगियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।''आपके पास जब बहुमत नहीं होता, तो आप सरकार बनाने में जल्दबाजी करते हैं। बहुमत होने पर सियासी पार्टियां आराम से काम करती हैं। इसलिए बीजेपी ने इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई। बीजेपी ये भी मैसेज देना चाहती है कि वो अपने पार्टनर्स को हल्के में नहीं ले रही, बल्कि उन्हें पूरा वक्त दे रही है।'
- 'शिवसेना तोड़ने के दौरान शिंदे ने कहा था कि उद्धव ने हिंदू अस्मिता के साथ समझौता करके कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया है। उन्होंने शिवसैनिकों को कमजोर किया है। शिंदे को शिवसैनिकों तक ये मैसेज देना था कि हम सत्ता के लिए किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। इसलिए सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये सब कुछ किया।''शिंदे जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि वे एक जुझारू नेता हैं और आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंच पर ये नहीं कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ा है। वे हमेशा यही कहते रहे कि वे सरकार बनाने में रोड़ा नहीं बनने वाले और मोदी-शाह की बात मानेंगे।''शिंदे ये जानते थे कि वे अगर पहले दिन ही सरेंडर कर देंगे तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। ये लगेगा कि उद्धव वाली शिवसेना से शिंदे वाली शिवसेना कमजोर है।'

बीजेपी ने भी फेस सेविंग के लिए शिंदे को भरपूर वक्त दिया

- 'ये बीजेपी के लिए भी फेस सेविंग रही। उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। वो जीत के बाद शिंदे को साइडलाइन कर सरकार बना लेगी।''यही वजह है कि बीजेपी ने ऐसा दिखाया कि वे शिंदे को पूरा सम्मान दे रहे हैं। अमित शाह ने शिंदे से अकेले में बात की। बीजेपी नेता भी लगातार उनसे मिलते रहे। अपने नाम का ऐलान होने से एक दिन पहले फडणवीस भी उनसे मिलने गए थे।

शिंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बदली

- सोर्स बताते हैं कि जिस दिन शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, गृहमंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे, उस दिन की तस्वीरों से बहुत कुछ साफ हो गया था। उसमें फडणवीस और अजित का चेहरा खिला हुआ था। वहीं शिंदे का चेहरा उतरा नजर आ रहा था। वे जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद न मिलने से वे दुखी हैं।गृह और वित्त मंत्रालय पर भी शिंदे को अमित शाह से ठोस भरोसा नहीं मिला। इन चर्चाओं से सबसे ज्यादा विचलित शिंदे के विधायक हुए। दो दिन बाद शिंदे के करीबी विधायक भरत गोगावले ने कन्फर्म भी किया कि शिंदे सरकार से बाहर रहना चाहते थे, लेकिन विधायकों के दबाव में ऐसा नहीं कर सके।

फडणवीस को मुख्यमंत्री बना बीजेपी ने कई पैटर्न बदले

2014 के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनने में जब भी 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लगाया, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सरप्राइजिंग चेहरे की एंट्री हुई है। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ये पैटर्न बदल दिया। महाराष्ट्र में उनका नाम बीजेपी में पहले से साफ था।दूसरा महाराष्ट्र में 46 साल में 9 डिप्टी मुख्यमंत्री बने, पर उनमें से किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। इस बार ये पैटर्न भी बदल गया है। फडणवीस डिप्टी रहने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं।

बीजेपी और आरएसएस की पहली पसंद फडणवीस ही रहे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ

1. आरएसएस का साथ

- फडणवीस को आरएसएस का सपोर्ट है। एक तो वे नागपुर से आते हैं, जहां आरएसएस का मुख्यालय है। दूसरा उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से ही की है। लोकसभा चुनाव के वक्त आरएसएस ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त संघ ने काफी मेहनत की। माना जाता है कि इसी वजह से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है।फडणवीस ने हमेशा आरएसएस के अनुशासन का पालन किया है। फायदे-नुकसान की परवाह किए बिना फडणवीस ने कभी भी आरएसएस का स्वयंसेवक होने की बात नहीं छिपाई। वे खुलकर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। विजयादशमी के समारोह में तो वे आरएसएस की फुल ड्रेस में शामिल होते हैं।

2. बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार

- महायुति की जीत में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका नकारी नहीं जा सकती है। 2014 से लेकर 2019 तक का उनका कार्यकाल अच्छा रहा। इसी का नतीजा था कि 2019 में बीजेपी - शिवसेना गठबंधन को जीत मिली। 2024 के नतीजे भी पार्टी के पक्ष में आए हैं।वे महायुति के स्टार प्रचारक थे। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों का सिलेक्शन तक फडणवीस ने किया। बाकी सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बैठाने का काम भी उन्होंने ही किया।

3. विरोधी पार्टियों को कमजोर किया

- सत्ता से बाहर रहते हुए भी फडणवीस ने 2019 के बाद ठाकरे सरकार को चैन से नहीं रहने दिया। माना जाता है कि शिवसेना और एनसीपी में बगावत की स्क्रिप्ट भी फडणवीस ने ही लिखी थी।उन्हीं की कोशिश से बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सभी विरोधी पार्टियों को कमजोर किया। उनकी बदौलत कभी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसलिए उन्हें पार्टी का असली चाणक्य कहा जा रहा है।

4. महायुति के नेताओं के साथ अच्छे संबंध

- देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता हैं, जिनके महायुति के लगभग सभी बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं। बीजेपी और आरएसएस ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सबको साथ लेकर चल सकते हैं और अगर कोई विवाद होता है तो उसे आसानी से सुलझा सकते हैं।

5. सरकार चलाने का अनुभव

- फडणवीस के पास बतौर मुख्यमंत्री सरकार चलाने का 5 साल और डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल का अनुभव है। महाराष्ट्र में विकास, हिंदुत्व और सभी जातियों को साथ लेकर सरकार चलाने की क्षमता फडणवीस की तुलना में महाराष्ट्र के बाकी नेताओं में नहीं है।

मुंबई में तय हुआ महाराष्ट्र का 'किंग'....पृष्ठ 10 पर

मुंबई में तय हुआ महाराष्ट्र का 'किंग'

देवाभाऊ बने महाराष्ट्र के नए सीएम

महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद नवंबर को आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। फडणवीस 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में फडणवीस ने राजभवन में फिर से शपथ ली थी लेकिन तब वह सिर्फ पांच दिन ही सीएम रहे पाए थे। देवेंद्र फडणवीस से अपने समर्थकों के लिए देवाभाऊ बने महाराष्ट्र के नए सीएम ने मां के नाम के साथ शपथ ग्रहण की। उन्होंने शपथ में मैं देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस... कह कर पद और गोपनीयता की शपथ ली।

देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में मौजूद थे।

बॉलीवुड हस्तियों में शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ समारोह में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी परिवार के साथ महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला भी शपथ समारोह में शामिल हुए।

मैं समंदर हूं लौटकर आऊंगा, सच कर दी वह बात

मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा !...ये लाइनें साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने तब कही थी, जब वह महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में बोल रहे थे। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए चुन लिए गए हैं, तब 5 साल पुरानी वह लाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है। 2014 में भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तब शिवसेना से गठबंधन टूट जाने के बाद भी भाजपा 122 सीटें जीती थी और राज्य में पहली बार फडणवीस के रूप में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री मिला था। उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ा गया। तब भी भाजपा 105 सीटें लेकर आई। मगर उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा देकर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बना ली।

शिंदे ने 6 महीने मुख्यमंत्री बनने का रखा था प्रस्ताव

बीजेपी के सोर्सेज ने बताया कि शिंदे ने अपनी आखिरी कोशिश 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के सामने की। शिंदे ने शुरू के ढाई साल खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी सरकार में 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला नहीं रहा है।हालांकि, अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन फडणवीस को काम करने दीजिए, उसके बाद आपके लिए भी गठबंधन ने अच्छा सोचा है। इसके बाद शिंदे को शाह की बात माननी पड़ी। शिंदे के पास अब ढाई साल बाद का ऑप्शन बचा है। हालांकि, हमारे सोर्स के मुताबिक अब तक बीजेपी के किसी नेता ने उन्हें लिखित या मौखिक भरोसा नहीं दिया है।

शिंदे को मिला था महायुति का संयोजक बनने का ऑफर

शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का कोई आश्वासन नहीं मिला था। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने 25 नवंबर को ये बात कन्फर्म भी की। उन्होंने कहा था कि महायुति के सरकार बनाने पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की कोई बात नहीं हुई थी।रामदास आठवले ने बताया कि बीजेपी आलाकमान ने शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनने की एवज में महायुति का संयोजक बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन शिंदे ने इसे ठुकरा दिया। आठवले ने कहा कि शिंदे को केंद्र में मंत्री बनने का प्रस्ताव भी दिया था। शिंदे ने महाराष्ट्र से बाहर जाने से इनकार कर दिया।उन्होंने कहा कि बैठक में अमित शाह ने शिंदे को बता दिया था कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा।

शिवसेना के बिना भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में

संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। इसके अलावा 13 विधायक ऐसे हैं, जो बीजेपी में रहे हैं, लेकिन उन्हें शिवसेना के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। एक इशारे पर वे बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं।इसके अलावा 5 निर्दलीय और अजित पवार के 41 विधायक पहले ही बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के पास 191 विधायक हैं, जो बहुमत के 145 के आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं।एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी मजबूत पोजिशन की वजह से बीजेपी को अब शिवसेना की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी चुनाव से पहले थी। यही वजह है कि बीजेपी मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय किसी भी हालत में उन्हें नहीं देने वाली है।

29 नवंबर — दोपहर को मुंबई लौटने के बाद शिंदे ने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दीं। ये जानकारी सामने आई कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई है।

29 नवंबर — शाम 5 बजे BJP प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्यपाल से मुलाकात कर 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की बात कही।

30 नवंबर — एकनाथ शिंदे ने खराब तबीयत का हवाला दिया और सतारा में अपने पैतृक गांव पहुंचे। दो दिन तक वे यहीं रहे।

2 दिसंबर — केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपानी को BJP ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया।

2 दिसंबर — शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां देखने के लिए BJP-NCP (अजित गुट) के नेता मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। अगले दिन शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता भी साथ थे।

3 दिसंबर — BJP के दोनों पर्यवेक्षक मुंबई पहुंचे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की।

4 दिसंबर — देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुने गए और दोपहर 3 बजे महायुति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया।

बिहार में अलर्ट पर जेडीयू!

शिवसेना जैसा खेल, खेल सकती है भाजपा

महाराष्ट्र में कुर्सी की अदला-बदली पर बिहार में हलचल,2025 में नीतीश का क्या होगा?

पटना। महाराष्ट्र में बीजेपी के पैंतरेबाजी से बिहार जदयू को भी इसी तरह की सत्ता के खेल का डर सता रहा है। आश्वासनों के बावजूद, अगर भाजपा बहुमत के करीब पहुंचती है तो जेडीयू को अपने भविष्य की चिंता है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक का असर बिहार पर भी पड़ रहा है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह लेने के बाद जेडीयू सतर्क हो गई है। भाजपा ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का आश्वासन दिया है। लेकिन जदयू को डर है कि अगर भाजपा को 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 के बहुमत के आंकड़े के करीब सीटें मिलती हैं, तो क्या भाजपा महाराष्ट्र प्रयोग दोहरा सकती है?

महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जदयू को चिंता है कि भाजपा बिहार में भी शिवसेना जैसा खेल, खेल सकती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने के भाजपा के आश्वासन के बावजूद जदयू सशंकित है। भाजपा की ताकत को जदयू स्वीकार करती है। मगर, बिहार में राजग की सफलता के लिए नीतीश कुमार के महत्व और मतदाता आधार को भी महत्वपूर्ण मानती है।

महाराष्ट्र में बिहार मॉडल नहीं चला

जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे के बिहार गठबंधन मॉडल को अपनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस मॉडल में भाजपा से कम सीटें जीतने के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बने रहते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे ने एनडीए का प्रचार किया था और सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे थे। 2020 के बिहार चुनावों में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिलीं, जो भाजपा की 74 सीटों से 31 कम थीं। फिर भी नीतीश को मुख्यमंत्री पद दिया गया था। लेकिन, महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद जेडीयू नीतीश के भविष्य पर विचार कर रही है।एक वरिष्ठ जेडीयू नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नीतीश सत्ता के भूखे नहीं हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण 2020 में मुख्यमंत्री बनने से शुरुआत में इनकार कर दिया था। जेडीयू नेता ने कहा, 2020 के नतीजों के बाद नीतीश ने पार्टी की संख्या का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बने रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन भाजपा नेताओं राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव ने उन पर जिम्मेदारी स्वीकार करने का दबाव डाला।

महाराष्ट्र मॉडल को लेकर जेडीयू अलर्ट

एक अन्य जेडीयू नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की घटनाओं के बाद पार्टी अस्थिर महसूस कर रही है, लेकिन बिहार एक अलग मामला है। उन्होंने कहा, शिंदे के पास विकल्पों की कमी थी क्योंकि शिवसेना के दोनों गुट हिंदुत्व का पालन करते हैं और उनका सामाजिक आधार जेडीयू से कमजोर है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू का 16.5% वोट शेयर था, जिससे एनडीए मजबूत हुआ। 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीतीं।जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, आप नीतीश कुमार से प्यार कर सकते हैं या नफरत, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन नीतीश की राजनीतिक ताकत को पहचानते हैं।

बीजेपी का नीतीश से सुविधा का विवाह

राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी ने कहा कि भाजपा बिहार में नीतीश की जगह नहीं ले सकती क्योंकि कोई विश्वसनीय विकल्प नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर नीतीश विपक्ष में शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा? चौधरी ने कहा, महाराष्ट्र में, शिंदे शक्तिहीन थे, लेकिन बिहार में हर कोई नीतीश को गले लगाएगा।एक अन्य विश्लेषक डीएम दिवाकर ने कहा कि भाजपा विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दिवाकर ने कहा, नीतीश और भाजपा एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते। उनका गठबंधन सुविधा का विवाह है।इस बीच, जेडीयू ने असम सरकार के गोमांस खाने पर प्रतिबंध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और खुद को भाजपा से अलग कर लिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, ऐसे फैसले समाज में तनाव बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान व्यक्तियों को अपना भोजन चुनने का अधिकार देता है और इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

एनडीए में आल इज नॉट वेल

सुदामा पांडेय धूमिल की एक कविता की ये पंक्तियां हैं- आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर तशरीफ सिर्फ बाएं हाथ से धोता है। धूमिल ने यह कविता चाहे जिस संदर्भ में लिखी हो, पर बिहार की सत्ता सियासत में यह फिट बैठती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दिया तो बिहार में उसकी इतनी महंगी कीमत वसूल रहे हैं, जितना भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीतीश की नजर में भाजपा कोटे के मंत्रियों का कोई मोल नहीं है। भाजपा ने भले अपने दो डेप्युटी सीएम बना कर नीतीश की नकेल कसने की व्यवस्था की थी, पर नीतीश के सामने उनकी कोई औकात नहीं। खासकर तब, जब केंद्र में सरकार बनाने लायक भाजपा को बहुमत नहीं मिला।नीतीश ने केंद्र द्वारा स्वीकृत उन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक की, जो बिहार से गुजरेंगी। पांच सौ से अधिक किलोमीटर सड़क बिहार के हिस्से की है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। सिन्हा बिहार के डेप्युटी सीएम भी हैं। आश्चर्य की बात है कि विजय सिन्हा को न विभागीय मंत्री के नाते बैठक में बुलाया गया और न डेप्युटी सीएम की हैसियत से ही नीतीश ने उनकी जरूरत महसूस की। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह कि बैठक में राज्यसभा सदस्य और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हुए। अगर सांसदों को भी शामिल करना था तो बाकी सांसदों को क्यों नहीं बुलाया गया। यह बात बिहार की सियासत में फिर एक बार चर्चा का विषय बनी हुई है। कयास लग रहे हैं कि एनडीए में आल इज नॉट वेल।

यह पहला मौका नहीं है, जब भाजपा कोटे के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की उपेक्षा हुई हो। लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया। कुछ में वे गए भी, मगर बैनर से उनकी तस्वीरें नदारद रहीं। इसके दो कारण हो सकते हैं। सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार की अनबन जाहिर है। विजय सिन्हा से भी नीतीश विधानसभा में उलझ गए थे, जब वे स्पीकर थे। जिन दिनों नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। सम्राट चौधरी ने बहैसियत भाजपा अध्यक्ष नीतीश को सीएम की कुर्सी से उतारने तक मुरैठा बांध रखा था। हालांकि नीतीश कुमार जब एनडीए में लौट आए और लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने पर नीतीश के साथ की जरूरत पड़ी तो तो सम्राट के सुर बदल गए। भाजपा में सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही भाजपा अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संभव है कि नीतीश के मन में अब भी यह बात बैठी हो।

अकल चबूतरे से

मुफ़्तखोरी और आत्मनिर्भरता के लिए सीनाज़ोरी

दिल्ली में प्रदूषण का आलम यह है कि हर दिल्ली वाला 49 सिगरेट स्मोकर अंदर रखा जा रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि दिल्ली में सरकार हर बंदे को मुफ्त में पिलावा रही है। भविष्य में कोई भी सरकारी मुफ़्त शराब पिलवाने का जुगाड़ भी करवा सकता है। कोई भी और सरकार कह सकती है कि फ्री शराब के साथ फ्री क्रेश्चन भी हम दे देंगे।तो वाला दिल्ली 49 सी.टी.आई. फ्री में पी रहा है, एक बंदे को मैंने देखा, वह एस.टी.एल. एक सी.टी.आई. सी.टी.आई. फ्री में पी रहा था। मैंने उनसे पूछा कि भाई 49 सितारा दिल्ली में आप ही फ्री मिल रही हैं, फिर भी तू ऊपर से और पी रही है।

व्यंग्य आलोक पुराणिक

सीता पीवक भाई ने कहा- देखिये, शहर में बहुत भंडारे रहते हैं, सबमें खाना मुफ्त है। पर अपने घर के खाने की बात कुछ और है। आत्मनिर्भर होना चाहिए बंदे को। तो भाई आत्मनिर्भरता के शौकीन हुए खुद उसे सीता पीता है, ताकि वह उन 49 पर असंतुलित न हो जाए, जो फ्री मिल रही हैं। फ्रीखोरी के साथ कुछ लोग आत्मनिर्भरता के प्रति भी पैदा होते हैं, यानी फ्री की सी.टी.एम. के साथ खुद की सी.टी.एम. भी कहते हैं ।फ्री में हर किसी को कुछ करना चाहिए, फ्री में किसी के लिए कुछ भी तैयार नहीं करना चाहिए। समय वह यह भी कह सकती है कि बेटे बाबा की मौत के बाद, बाप का बोझ उठाने से मना कर दिया और कह दिया कि फ्री में क्यों उठाऊं, मुझे क्या मिलेगा। मुफ़्तखोरी की गारंटी बहुत कुछ बदल देती है। फ्रीखोर कुछ करने को तैयार ना होता, सीता पीने के साथ। संग्रहालय कथाकार प्रेमचंद की एक कहानी है कफ़न। इस कहानी में दो रिश्ते हैं-घीसू और माधव, ये दोनों परम कामचोर बंदे हैं, कुछ नहीं करते। इस कादर गैर-जिम्मेदार के परिवार की एक महिला की मौत के कफन के लिए मिले डॉक्टरों से भी दारू पी जाते हैं। फिर दोनों बातें करते हैं, बात का सारा ये होता है कि चिंता मत करो, कोई ना फिर पैसा मांगेगा, कफ़न के लिए। भारतीय परंपरा में उच्च मित्र के मुफ़्तखोर रह रहे हैं, घीसू माधव की कविता। न करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गया साक्षात दाता राम-यानी संदेश साफ है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंछी भी कुछ काम नहीं करता है और पंछी भी कुछ काम नहीं करता है। पर साहब, ड्रैगन को बड़ी कार में चलने की चाहत भी नहीं थी। ड्रैगन को बड़े घर की दरकार नहीं होती। ड्रैगन को डैमेज शराब की चाहत नहीं होती। इंसान को होता है, इन सब वस्तुओं की चाहत, तो उसका हिसाब-किताब अलग होता है ड्रैगन संतोषी जीव होता है, इंसान नहीं होता। भारतीय इंसान तो अब संतोषी नहीं रहा। कहीं उसे मुफ़्त चावल मिल रही है, कहीं उसे मुफ़्त सीता मिल मिल रही है। हर इंसान पर ऐसा नहीं है, जी फ्री की 49 सीता मिल रही हैं दिल्ली में फिर भी आपको दिल्ली में कोई न कोई सिगरेट पीटता हुआ ही मिलता है, आत्मनिर्भरता की कसम।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर जारी

मध्यप्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी की हार के बाद मंत्री रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वही राज्यपाल ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद से मोहन सरकर में एक और मंत्री पद खाली हो गया है। सरकार में अब केवल 31 मंत्री बचे हुए है। रामनिवास रावत का वन मंत्रालय अब सीएम मोहन यादव के पास पहुंच गया है। नियम के अनुसार किसी मंत्रालय के मंत्री के इस्तीफे के बाद स्वत: ही वह मंत्रालय सीएम के पास पहुंच जाता है ।रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर वन मंत्रालय अब किसे सौंपा जाएगा। इसके अलावा कयास लगाए जा रहे है कि मोहन सरकार नए साल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। सरकार में अभी 31 मंत्री है, नियम अनुसार सरकार में 35 मंत्री बनाए जा सकते है। यानी सरकार में 4 मंत्रियों की कुर्सी खाली है। रावत के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है कि वन मंत्रालय किसे मिलेगा ? इसको लेकर कयास लगाए जा रहे है कि अगर मोहन सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो अमरवाड़ा से भाजपा विधायक कमलेश शाह को वन मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल, राम निवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मोहन सरकार ने रावत को सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया था।

वही अमरवाड़ा से भाजपा विधायक कमलेश शाह कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा और विधायक बने। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार कमलेश शाह को सरकार में मंत्री बनाकर मौका दे सकती है। आपको बता दें कि रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद वन मंत्रायल का प्रभार सीएम मोहन यादव के पास रहेगा। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तब तक सीएम मोहन वन मंत्रालय देखेंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, होगा या नहीं यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर जारी है।

उमंग सिंघार बोले... जो योजनाएं चल रही उसमें नया कुछ नहीं, जिन योजनाओं में घोटाले हुए उन पर मौन

मध्यप्रदेश के डॉ मोहन यादव सरकार के एक साल पूरा होने पर जारी रिपोर्ट कार्ड पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सियासी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर बोले- जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ नहीं है। जिन योजनाओं में घोटाले हुए उन पर वह मौन रहे। विपक्ष के मुद्दों पर सीएम ने कोई बात नहीं की है। चुनाव में लाडली बहना को लेकर 3000 के पोस्टर लगे लेकिन अब तक नहीं दिए गए। कब 3 हजार करेंगे उसका जवाब सीएम को देना चाहिए। इसी तरह प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। सरकार गौ माता की बात कर रही है लेकिन आज भी सड़कों पर गाये एक्सीडेंट में मर रही है, उसकी जवाबदेही सरकार ने आजतक तय नहीं की है ।उमंग सिंघार ने कहा कि- बीजेपी की सरकार ने एक साल में योजनाएं तक सही से नहीं चलाई है। एयर एम्बुलेंस का फायदा गरीबों को नहीं केवल अमीरों और उद्योगपतियों को इसका फायदा मिलता है। यह योजना केवल कागजों पर है। प्रदेश में अबतक बैकलॉक की भर्ती नहीं हुई न 2 लाख रोजगार दिए गए। इसी तरह अपराध को रोकने के लिए नई भर्ती की आवश्यकता है लेकिन सरकार ने अब तक भर्ती नहीं की है। ब्लॉक स्तर पर डॉक्टर्स की कमी है लेकिन घोटालों की परीक्षा करवाई जा रही है। हाइकोर्ट की फटकार के बाद भी नर्सिंग घोटाले पर कार्यवाही नहीं हुई। किसान खाद के लिए परेशान है कृषि मंत्री को खाद के मामले की जानकारी ही नहीं है।

बीना सीट पर होगा उपचुनाव, निर्मला सप्रे ने शुरू की तैयारी?

मध्यप्रदेश की दो विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी और मोहन सरकार के मंत्री रामनिवास रावत को करारी शिकस्त दी। जिसके बाद से कांग्रेस बीना सीट पर उपचुनाव की मांग करती आ रही है। वही बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे की मांग भी जोरो से की जा रही है। जानकारी के अनुसार बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे ने अपनी विकास यात्रा फिर से शुरू कर दी है। इस दौरान वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यो की सौगात भी देंगी। सप्रे की यह विकास यात्रा भाजपा के बैनर तले होगी। ऐसे में निर्मला सप्रे की भाजपा के बैनर तले विकास यात्रा को उपचुनाव होने के तौर पर देखा जा रहा है। विकास यात्रा 20 दिसंबर तक चलेगी। बीना विधायक निर्मला सप्रे की इस विकास यात्रा को

लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि निर्मला सप्रे उपचुनाव की तैयारी कर रही है। निर्मला ने बीते दिनों भोपाल में भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद निर्मला सप्रे विकास यात्रा लेकर निकल रही है। कहीं न कहीं उनकी यह यात्रा उपचुनाव होने के संकेत देती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे के खिलाफ उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और संबंधित को नोटिस भी जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि निर्मला सप्रे ने बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और विधायक चुनी गई थी, लेकिन निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान सागर के राहतगढ़ में हुई एक चुनावी सभा में सीएम मोहन के समाने वे बीजेपी में शामिल हो गई थी।

कही-सुनी

कीर्ति राणा

जीते जी मार डाला आईएएस....

परिवारवालों से लेकर आईएएस लॉबी तक हत्प्रभ है कि आईएएस सृष्टि देशमुख के निधन की खबर कैसे, किसने, क्यों वॉयरल की जबकि सृष्टि जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और खुद उन्होंने अब सायबर सेल के साथ ही नरसिंहपुर पुलिस से उनकी मौत संबंधी इस झूठी खबर की सच्चाई पता करने का आवेदन भी दे दिया है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एसडीएम पदस्थ सृष्टि देशमुख के निधन की इस झूठी खबर को सच मान बैठे लोगों ने श्रद्धांजली देने में विलंब भी नहीं किया।भोपाल निवासी देशमुख परिवार की पुत्री सृष्टि ने यूपीएससी परीक्षा 2018 में देश में पांचवीं और महिला वर्ग में पहली रैंक हांसिल की थी।सोशल मीडिया पर दीपावली के आसपास उनके निधन की खबर वॉयरल हुई, तब से यह सिलसिला चल रहा है।यह मान्यता है कि निधन की झूठी खबर से उम्र बढ़ जाती है लेकिन इससे उपजा तनाव कितना पीड़ादायी होता है इसे देशमुख परिवार ही जानता है। अब तेजी से जांच हो तब ही पता चल सकता है ऐसी खबर क्यों फैलाई गई।

प्रदर्शन में यह चिंतन भी

बांग्लादेश में अल्पंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ इंदौर के लालबाग में भी डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों में यह भी चर्चा रही कि हमें प्रदर्शन करने की नौबत ही नहीं आती यदि वहां मची उथल-पुथल के दिन से ही हमारी सरकार रवैया सख्त रखती, शेख हसीना को शरण नहीं देती।लोगों की यह भी प्रतिक्रिया थी कि प्रदर्शन कर के हम अपनी सरकार की ही ढिलाई का विरोध कर रहे हैं।लालबाग में जुटने वाली भीड़ में इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले भी तब चुप हो जाते थे जब भगवा ध्वज थामे नेता अपने समर्थकों के साथ पास आते दिखते थे।

86 में से 4, इनमें से एक कौन ?

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के अगले कुल गुरु के लिये 86 आवेदनों में से तीन सदस्यीय चयन समिति ने 4 नामों का पेनल बनाया है। तय किये गये चार नाम में विजय मनोहर तिवारी, विकास दवे, आशीष जोशी और प्रो अनिल कुमार सौमित्र हैं। इन चारों में से किसी एक का नाम मुख्यमंत्री को तय करना है। बहुत संभव है कि 15 दिसंबर तक घोषणा हो जाए। अभी जो कुलगुरु थे प्रो केजी सुरेश बंगले से पर्दे-बर्तन आदि सामान साथ ले जाने और उनसे पहले रहे प्रो बृज किशोर कुठियाला भी कुछ ऐसे ही विवादों के कारण चर्चा में रहे थे।

क्षिप्रा के सेवकों पर भारी जिम्मेदारी

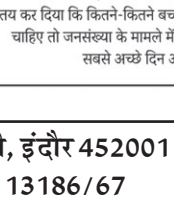

इस बार के सिंहस्थ और सरकार को मणि-कांचन संयोग कहने में हर्ज नहीं।पहले भी भाजपा को सिंहस्थ कराने का अवसर मिलता रहा है। 2028 के सिंहस्थ में जो खास रहना है वह यह कि मुख्यमंत्री यादव भी इसी शहर के हैं। सिंहस्थ चाहे 2004 का रहा या 2016 का क्षिप्रा को सदा नीरा दिखाने के लिये टैंकरों से पानी छोड़ा जाता था।तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक ने क्षिप्रा को गंदगी मुक्त करने के ठोस प्रयास नहीं किए।2028 के सिंहस्थ में विश्व से आने वाले श्रद्धालुओं की मेजबानी मुख्यमंत्री यादव करेंगे तब उनके लिये श्रद्धालुओं को क्षिप्रा के जल में ही स्नान कराने की चुनौती भी रहेगी।ऐसा नहीं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिये कुछ नहीं किया बीते दो सिंहस्थ (24 साल में) अरबों खर्च हो चुके हैं। अब जो राशि क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिये खर्च होगी उसका उपयोग सही नहीं हुआ तो सरकार के मुखिया पर भी आंच आएगी, इस गंभीरता को मुख्यमंत्री भी जानते हैं वो खुद क्षिप्रा के उदगम से बहाव क्षेत्र तक की यात्रा कर चुके हैं, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर नातू भी क्षिप्रा बहाव क्षेत्र की पदयात्रा कर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं तो क्षिप्रा के उद्धार के लिये सही अर्थों में इस बार ही काम होगा।

पीटा भाजपाइयों ने फंसाया कांग्रेसियों को !

महिदपुर में भाजपा के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान के साथ मारपीट करने वाले भी पार्टी के ही लोग थे, वीडियो में इस की पुष्टि भी हो गई लेकिन इस पिटाई कांड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम एफआईआर में लिखाए जाने से कांग्रेस नेताओं का भड़कना स्वाभाविक ही है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एफआईआर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी देकर कुछ गलत भी नहीं किया। वीडियो में भी स्पष्ट हो गया कि पूर्व विधायक चौहान के साथ मारपीट करने वाला सौदान सिंह भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला है।

मतदाताओं ने नकारा, सरकार पुचकारे

विजयनगर उपचुनाव में मतदाताओं द्वारा नकार दिये जाने के बाद पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत समझ नहीं पार हे हैं कि उन्हें नागर सिंह चौहान की बुरी नजर लग गई या भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विश्वास लायक नहीं समझा। अब उनकी सारी उम्मीद मुख्यमंत्री यादव पर टिकी है। पुनर्वास में निगम-मंडल में कहीं मौका मिल जाए तो ठसक बनी रहेगी। ऐसा सम्मान पाना तभी आसान हो सकता है जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में प्रेम उमड़ने लगे वैसे विजय नगर चुनाव प्रचार को लेकर वह साफ कह चुके हैं कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं इसलिये गया भी नहीं।सिंधिया के इस बयान की हवा प्रदेश भाजपा कार्यालय प्रभारी भगवानदास सबनानी ने यह कह कर निकाल चुके हैं कि सिंधिया को बुलाया गया था। लेकिन वो गये ही नहीं।

नेता का वादा बह गया साथ

सीधी की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर लीला साहू पांच महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी से अपने गांव की सड़क बनवा देने की गुहार लगाने वाले वीडियो के कारण चर्चा में रही थी। तब क्षेत्रीय सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने वादा किया था कि नवंबर से उनके गांव की सड़क का काम शुरु हो जाएगा। नवंबर बीत गया, सड़क तो बनी नहीं। लीला साहू ने नया वीडियो जारी कर दिया है। इसमें वो कह रही हैं-'आपको क्या लगता था, हम नहीं लौटेंगे? जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं, तब तक नेता जी को छोड़ेंगे नहीं.. गई नवंबर, गई बरसात, नेता का वादा बह गया साथ।

तीन या चार, आखिर कितने करें ?

बागेश्वरधाम वाले पं. धीरेंद्र शास्त्री ने करेरा (शिवपुरी) में देश में घटती हिंदुओं की संख्या में वृद्धि के लिए चार बच्चे पैदा करने और इनमें से दो सनातन धर्म के लिए समर्पित करने का आह्वान कर दिया है। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत तीन बच्चे पैदा करने की सलाह दे चुके हैं।हम इतने संतों-शंकराचार्यों-धर्मगुरुओं में आस्था रखते हैं यदि सबने अपने हिसाब से तय कर दिया कि कितने-कितने बच्चे पैदा करना चाहिए तो जनसंख्या के मामले में तो भारत के सबसे अच्छे दिन आ ही जाएंगे।

खाद से ज्यादा ज्ञान का संकट

प्रदेश में खाद संकट चर्चा का मुद्दा इसलिये भी नहीं होना चाहिये कि यह हर सरकार में रहता आया है। इस सरकार में खाद से ज्यादा तो ज्ञान का संकट चर्चा में है।खाद का सीधा ताल्लुक कृषि मंत्रालय से है जिसकी जिम्मेदारी सीधे-सीधे कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की है। कृषि मंत्री ही सार्वजनिक रुप से कहें कि वितरण गड़बड़ी के लिये उर्वरक और सहकारिता विभाग जिम्मेदार है तो यह ज्ञान का संकट ही माना जाएगा ना क्योंकि वितरण कराने का दायित्व तो कृषि विभाग का ही है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67